दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा अपेक्षाकृत कम वजन की गेहूं, चावल और चीनी की बोरियों की सप्लाई

2616. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के ठेकेदारों ने उचित दर दुकानों को कम वजन की गेहूं, चावल की बोरियों की सप्लाई करके उनके डीलरों के साथ हेराफेरी करने की प्रथा बना ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) दिल्ली पुलिस ने इससे इंकार किया है तथापि, जब कभी कम तोल की शिकायत प्राप्त होती है, दिल्ली प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समय पर राशन कार्ड जारी न किए जाने के विरुद्ध शिकायतें

2617. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन के मंडल संख्या 42 और मण्डल संख्या 2 (पूर्वी भाग) के मंडल निरीक्षकों के खिलाफ इस बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने राशन कार्डों के लिए आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के 72 घंटों के बाद नए राशन कार्ड जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 72 घंटे के बाद राशन कार्ड जारी करने में हुए इस विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) उन आवेदकों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें 72 घंटों के बाद राशन कार्ड जारी किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार इन दोषी निरीक्षकों को निलम्बित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि खाद्य कार्ड के लिए किसी भी आवेदक से इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Grant-in-aid for improvement of educational and social economic conditions of SC|ST in Orissa

2618. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are giving grants-in-aid to Violuntary Organisations in the backward States;

(b) whether such grant-in-aid is being given for improvement of educational and socio-economic conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) if so, the number of such organisations in Orissa which are receiving grants-in-aid and the total amonut of grant-in-aid received by those organisations during the last three years; and